भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 5631
दिनांक 04.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक

5631. **श्री पी. पी. चौधरीः**
श्री तेजस्वी सूर्याः
श्री पी. सी. मोहनः
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः
श्री जगदम्बिका पालः
श्री धर्मबीर सिंहः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्री की नए अमेरिकी प्रशासन के साथ पहली द्विपक्षीय बैठक के दौरान, विशेष रूप से रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग के संबंध में क्या विशिष्ट समझौते हुए और सहमति बनी;

(ख) क्या भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत-अमेरिका सहयोग को मजबूत करने के लिए कोई रूपरेखा स्थापित की गई है और यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन के लिए प्रमुख ध्यान वाले क्षेत्र और तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग सहित महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग के लिए कोई ढांचा विकसित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जनवरी 2025 में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के प्रमुख परिणाम क्या हैं और साथ ही भारत के विशिष्ट योगदान और प्रतिबद्धताओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) विदेश मंत्री ने 20 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में उनका प्रतिनिधित्व किया। द्विपक्षीय बातचीत के दौरान, दोनों पक्षों ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सहयोग, ऊर्जा, शिक्षा और वैध आवाजाही में भारत-अमेरिका सहभागिता को और प्रगाढ़ बनाने के अवसरों के साथ-साथ अनेक विषयों पर चर्चा की गई। इस यात्रा के दौरान कोई विशेष द्विपक्षीय करार संपन्न नहीं किया गया।

क्वाड विदेश मंत्रियों ने 21 जनवरी 2025 को वाशिंगटन डी.सी. में मुलाकात की और एक स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत को मजबूत बनाने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जहां कानून का शासन, लोकतांत्रिक मूल्य, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित किया जाए और इसकी रक्षा की जाए। उन्होंने इस पर महत्व जताया कि अंतरराष्ट्रीय कानून, आर्थिक अवसर, शांति, स्थिरता और समुद्री क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में सुरक्षा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लोगों के विकास और समृद्धि का आधार हैं। मंत्रियों ने ऐसी किसी भी एकपक्षीय कार्रवाई का कड़ा विरोध भी किया जिससे बल या दबाव के जरिए यथास्थिति में परिवर्तन करने की चेष्टा की जाए। वे क्षेत्रीय समुद्री, आर्थिक और प्रौद्योगिकी सुरक्षा को मजबूत बनाने के साथ-साथ विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने और 2025 में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले अगले क्वाड लीडर्स समिट की तैयारी में क्वाड के लिए कार्य करने पर सहमत हुए।

****